

प्रपक,

मोहम्मद शाहिद,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
देहरादून।

समाज (अल्पसंख्यक) कल्याण अनुभाग-3

देहरादून : दिनांक 30 दिसम्बर, 2014

विषय-वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद हरिद्वार के ब्लॉक भगवानपुर (सिरचण्डी) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपयुक्त विषयक, अपने पत्रांक-1142 नि.स.क./एम.एस.डी.पी./डी.पी.आर./14-15 दिनांक 12.11.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा जनपद हरिद्वार के ब्लॉक भगवानपुर (सिरचण्डी) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम, हरिद्वार द्वारा गठित आंगणन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। भारत सरकार के शासनादेश संख्या-3/20(4)/2013-पी०पी०-1 दिनांक 19.09.2014 की छायाप्रति संलग्न करते हुए अवगत कराना है कि भारत सरकार को शासनादेश दिनांक 19.09.2014 के साथ संलग्न परिशिष्ट-1 की तालिका 2 के क्रमांक-2 पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु कुल ₹ 132.04 लाख अनुमोदित करते हुए केन्द्रांश ₹ 99.03 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में ₹ 49.51 लाख की धनराशि अवमुक्त की है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हरिद्वार के भगवानपुर (सिरचण्डी) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था 'उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, हरिद्वार' द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर टी०ए०सी० द्वारा आंगणन के तकनीकी परीक्षणोपरान्त सन्तुष्ट लागत ₹ 132.37 लाख (सिविल कार्य हेतु ₹ 124.70 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्य हेतु ₹ 7.67 लाख) के क्रम में, भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत कार्य की अनुमोदित लागत को दृष्टिगत रखते हुये वर्तमान में ₹ 07.34 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार + सिविल कार्य हेतु ₹ 124.70 लाख अर्थात् कुल धनराशि ₹ 132.04 लाख (₹ एक करोड़ बत्तीस लाख चार हजार मात्र) की औचित्यपूर्ण धनराशि पर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त प्रथम किश्त ₹ 49.51 लाख (₹ उन्पचास लाख इकावन हजार मात्र) एवं राज्यांश 18.50 लाख (₹ सोलह लाख पचास हजार मात्र) कुल ₹ 66.01 लाख (₹ छियासठ लाख एक हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

1. उक्त कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-4/5/XXVII(7)/2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एन०ओ०यू० अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाये। उक्तानुसार निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण कराकर भवन विभाग को हस्तान्तरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र, दिनांक 19.09.2014 द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों एवं एम०एस०डी०पी० की गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उ०प्र०रा०नि० निगम द्वारा एम०ओ०यू० में निर्धारित समय के अंतर्गत भवन कार्य प्रत्येक दश में पूर्ण कर भवन हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न करा ली जाये।

3. परीक्षण के सन्दर्भ में नियोजन विभाग से समन्वय कर, परीक्षण सम्पन्न कराते हुए कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी एवं उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय कार्यदायी संस्था की देय सेन्ट्रल चार्ज से वहन किया जायेगा। गुणवत्ता परीक्षण आस्था शासन को भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका बजट मैनुअल के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त कस्के ही किया जाए। कार्य हेतु पूर्व अयमुक्त धनराशि के पूर्व संतोषजनक व्यय विषयक आस्था प्राप्त होने पर ही वर्तमान में स्वीकृत धनराशि आहरित/व्यय की जायेगी।
5. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य नई मदों में कदापि नहीं किया जायेगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है। आगणन में प्राक्खानित व्यय करने से पूर्व उक्त हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में निहित उपबन्धों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। अव्ययित अवशेष धनराशि राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यदि अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत अधिक धनराशि की आवश्यकता पड़ती है तो चिकित्सा विभाग के सुसंगत लेखा शीर्षकों/मदों से इसकी पूर्ति सुनिश्चित करादी जायेगी।
6. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित दरों को जो दर शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से की गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
7. एक नुस्त प्राविधान के कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
8. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुये एवं जोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।
9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद को दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
10. यदि स्वीकृति राशि में स्थल विकास कार्य सम्मथ न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मासवित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाए।
11. कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुये कार्य को समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। जी०पी० डब्लू० फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।
12. स्वीकृत उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को अयमुक्त करने से पूर्व प्ररनगत योजना हेतु भूमि की उपलब्धता की पुष्टि करनी आवश्यक होगी। किसी भी दशा में भूमि उपलब्ध होने से पूर्व उक्त स्वीकृत धनराशि जारी न की जाय।
13. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-15 के लेखाशीर्षक-2250-अन्य सामाजिक सेवाएँ-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरानिधानित योजनाएँ-01-अल्पसंख्यकों हेतु मन्त्री सेक्टरल विकास योजना के मानक मद-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।
14. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-266(P)/XXVII(3)/2014-15, दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति तथा अलोटमेंट आई.टी. संख्या-SI412150288, दिनांक 27 दिसम्बर, 2014 के कम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मोहम्मद शाहिद)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:- // ५५ / XVII-3/14-07(17-MSDP)/2014 : तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/ सचिव चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार।
6. महाप्रबन्धक, उ०प्र० रा० नि० लि०, ई० 34 नेहरू कालोनी देहरादून।
7. नोडल अधिकारी/उप सचिव (एम०एस०डी०पी०), उत्तराखण्ड शासन।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
9. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।
10. एन.आई०सी, सचिवालय परिसर।
11. विभागीय आदेश पुरितका।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
संयुक्त सचिव।

बजट अवधि वित्तीय वर्ष - 2014-2015

Secretary, Minority Welfare (5064)

आवक संख्या - 1145/XVII-3/14-07(17-MSDP)/2014

अन्योन्य आई टी - S1412150288

अनुदान संख्या - 015

आवक संख्या - 27-Dec-2014

HOD Name - Director Minority Welfare (4132)

विषय शीर्षक	2250 - अन्य सामाजिक सेवाएं 800 - अन्य आय 01 - सामाजिक सेवाएं हेतु राष्ट्रीय संस्कार विकास योजना (60)	00 - 01 - बजट अनुदान/अनुदान/अनुदान
-------------	--	---------------------------------------

Plan Voted

आवक संख्या का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - सामाजिक सेवाएं/अनुदान/अनुदान	169170200	6601000	175771200
	169170200	6601000	175771200

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

6601000


(बी.एस.डी. बोरा)
अ.स. सचिव
सामाजिक कल्याण विभाग
सांख्यिक महानगर